to thwart this bid by a section of the blanket manufacturers to seek profitable outlets for their products ; and

(c) who are the members of this syndicate who have devised such means of cheating the Government and Defence personnel ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI K.P. SINGH DEO) : (a) Yes, Sir. We have, however, no information to substantiate the reported formation or operation of an informal syndicate for supplying sub-standard blankets to the Defence Department, as mentioned in the news item referred to.

(b) and (c). Do not arise in view of the answer given to part (a) of the Question.

Pak-Bangladesh Fresh Bid for Defence Pact

3448. SHRI SANAT KUMAR MANDAL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Pakistan has reportedly made a fresh bid for a defence pact with Bangladesh ;

(b) if so, whether Government have studied its impact on India's security and sovereignty ; and

(c) the steps being taken to meet this new threat posed by the revival of the Pak-Bangla defence pact plan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI K.P. SINGH DEO) : (a) to (c). While there have been some press reports, Government have no confirmed information on the subject.

Government maintain a watch on all developments likely to affect India's security interests and take all necessary steps to safeguard them.

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

3449. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को देश में क, ख और ग क्षेत्र के सभी राज्यों में द्विभाषिक रूप से कार्यान्वित करने का उपबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय, उनके विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और क, ख, ग, क्षेत्रों के राज्यों में स्थित उपक्रमों में 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में धारा 3(3) के कार्यान्वयन की प्रतिशतता का वर्ष-वार और राज्यवार ब्योरा क्या है ;

(ग) उक्त सभी तीन क्षेत्रों में उक्त सभी 14 मुद्दों का शत-प्रतिशत कार्य द्विभाषिक करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते । जहां तक मंत्रालय का संबंध है, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 (दिसम्बर, 1983 तक) के दौरान राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों का कार्यान्वयन किया जाता रहा है। संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों के संबंध में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं ।

(ग) कोई विशिष्ट कठिनाई नहीं महसूस की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

3450. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :